



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

80  
२१/१

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 1989/ज्येष्ठ 29, 1911

No. 359]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 1989/JYAISTHA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ में द्वारा दाती है जिससे कि यह धारणा संक्षेप के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

प्रधिकृतवता

नई दिल्ली, 19 जून, 1989

का.प्रा. 467(य).—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकारता  
अवरोधक अधिकारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969  
का 54) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा  
गया है) को धारा 22 को उत्तराधि (1) के वर्ग  
(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह  
नियंत्रण देती है कि इस अधिकृतवता के वैश 2 और 3  
में विनियिष्ट शर्तों के अंतर्गत रहते हुए, अधिनियम को धारा  
21 और 22 के उपबन्ध प्रस्तावों के नियन्त्रिता  
प्रवर्गों को नागू नहीं होगी, अर्थात्:—

1. (i) कोई ऐसा प्रसाद जो हिस्सों एवं नागू  
उपक्रम के पर्याप्त प्रसारण या व्यापन से मंबंधित है

1653 GI/89

जिसमें भारत में पूर्णांग विकास किसी श्रोतोंको  
की वाणिज्यिक उत्पादन अन्वेषित है किन्तु उनको जोड़कर  
जिसमें कोई ऐसा अन्तर्गत हो जा—

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) प्रयोगिता, 1951  
(1951 का 65) को धारा 29 को उत्तरा

(26) के व्यापार अधिकृतवता द्वारा लवृ  
औद्योगिक उपक्रमों द्वारा अन्तर्गत उपस्थिति  
के लिए आवश्यक है या आरक्षित हो जा  
सकती है;

अथवा

(ख) अधिनियम को अनुमूली के भाग 1 में, विनि-  
यिष्ट किसी उद्योग से संबंधित है।

(ii) कोई ऐसा प्रस्ताव जो उकायों के प्राप्तवात  
और विकास एकान्में पूर्णतः विकास किसी  
श्रोतोंको के अन्तरण से संबंधित हो।

(1)

2. (i) उपक्रम का स्वामी, प्रस्ताव करने वाला अधिकारी प्राधिकारी (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1975 के नियम 6 खं के अधीन गठित) द्वारा प्रोत्योगिकी और से भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग को इस आवश्यक प्रमाणन्त्र प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव पूर्णतः भारत में विकासित किसी प्रोत्योगिकी पर अधिकृत है।

(ii) उपक्रम का स्वामी, प्रस्ताव करने वाला अधिकारी प्राधिकारी भारत सरकार के कार्य विभाग का जायजग में जिसमें प्रस्ताव के और और तथा इसके साथ हो उद्योग (विकास और वित्तन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन आवेद की, जहां कही किया जाना अपेक्षित हो, प्रति भी भजेगा।

(iii) उपक्रम का स्वामी, प्रस्ताव करने वाला अधिकारी प्राधिकारी उसी मद के लिए विदेश से किसी प्रोत्योगिकी का जायात नहीं करेगा।

3. पैरा 1 के उपर्युक्त (i) के अंतर्गत आने वाले किसी प्रस्ताव के बारे में, निम्नान्वित गति में तात्पूर होगा, अर्थात्—

यह कि औद्योगिक उपक्रम किसी ऐसे नगर या कस्बे के 50 किलोमीटर को दूरी के भीतर स्थित नहीं है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, किसी ऐसे नगर या कस्बे के 30 किलोमीटर को दूरी के भीतर स्थित नहीं है जिसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख से कम है, किसी ऐसे नगर या कस्बे के 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित नहीं है, जिसकी जनसंख्या 7.5 लाख से अधिक किन्तु 15 लाख से कम है और वह किसी ऐसे नगर या कस्बे का नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित नहीं है, जिसकी जनसंख्या 7.5 लाख से कम है।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रकाशी रहेगी।

[फा०स० 5/62/88 एम.आई.]  
ए.सी. गोयल, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Company Affairs)  
NOTIFICATION  
New Delhi, the 19th June 1989

S.O. 467(E).—In exercise of the report conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 22A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby directs that subject to the conditions specified in paragraphs

2 and 3 of this notification, the provisions of sections 21 and 22 of the Act shall not apply to the following categories of proposals, namely :—

1. (i) Any proposal that relates to the substantial expansion or establishment of a new undertaking involving commercial utilisation of a technology totally developed in India but excluding the one involving any article,—

(a) that is or may be reserved for exclusive production by small-scale industrial undertaking by a notification under sub-section (2A) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951); or

(b) that relates to any industry specified in Part I of the Schedule to the Act.

(ii) Any proposal that relates to the transfer of a technology totally developed in the undertakings' Research and Development unit.

2. (i) The owner of the undertaking, person or the authority making the proposal, shall submit a certificate from the Board of Indigenous Technology (constituted under Rule 6B of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970) to the Government of India in the Department of Company Affairs, to the effect that the proposal is based totally on a technology developed in India.

(ii) The owner of the undertaking, person or authority making the proposal shall submit to the Government of India in the Department of Company Affairs, a memorandum containing details of the proposal, alongwith a copy of their application, wherever required to be made, under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

(iii) The owner of the undertaking, person or authority making the proposal shall not import any technology from abroad for the same item.

3. In regard to any proposal falling under clause (i) of paragraph 1, the following condition shall also apply,—

That the industrial undertaking is not located within a distance of 50 kilometres a city or town having a population exceeding 25 lakhs, 30 kilometres of a city or town having a population exceeding 15 lakhs but less than 25 lakhs, 15 kilometres of a city or town having a population exceeding 7.5 lakhs but less than 15 lakhs and outside municipal limits of a city or town having a population of less than 7.5 lakhs.

4. This notification shall have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 5/62/88-M.L.]  
L. C. GOYAL, Dy. Secy.